रणजीत टाइम्स

वर्ष : 1, अंक: 96 इंदौर, शनिवार 5 अप्रैल 2025

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

DIGITAL EDITION

भारत की '7 बहनें' बनेंगी

एशिया के लिए तरक्की का रास्ता!

● बिम्सटेक में बड़ा प्लान, हाथ मलते रह जाएंगे चीन और बांग्लादेश ● बिम्सटेक के जरिए साउथ-ईस्ट एशिया से जुड़ने का नया प्रोजेक्ट

बैंकॉक (एजेंसी)। बीजिंग में नॉर्थ-ईस्ट का जिक्र कर मोहम्मद यूनुस ने चीन को आगे कर भारत को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा प्लान पेश करने वाले हैं, जिससे ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दुनिया के कई देशों के लिए विकास का दरवाजा खुलेगा, बल्कि बांग्लादेश ने जो बेशर्म हरकत की थी, उसे भी करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्लान से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी क्रांति होने वाली है। एक वक्त था जब पूर्वोत्तर भारत खराब सड़कें और खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से अपने नसीब पर

आंसू बहाता था लेकिन आज की तारीख में पूर्वोत्तर भारत में बेहतरीन सड़कों और पुलों का जाल बिछा दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत में रेल प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाया गया है।

बिम्सटेक के एजेंडे में भारत का महाप्लान

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान भारत सरकार के इस प्लान का जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद यूनुस को आईना दिखाते हुए दोटूक शब्दों में कहा कि भारत की बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा है, जो लगभग 6500 किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत न सिर्फ पांच बिम्सटेक सदस्यों के साथ सीमा साझा करता है, बल्कि उनमें से ज्यादातर देशों को जोड़ता भी है। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप और आसियान के बीच बहुत ज्यादा इंटरफेस भी प्रदान करता है। आपको बता दें कि बिम्सटेक देशों की संयुक्त आबादी करीब 1.73 अरब है और ये सभी दिश मिलकर 5.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाते हैं।

खंडवा में एक साथ जलीं 8 चिताएं, बेटी ने दी मुखाग्नि

● कुएं में जहरीली गैस से हुई थी मौत, एक को बचाने में गई 7 की जान

भोपाल। खंडवा के कोंडावत गांव में शुक्रवार सुबह एक साथ 8 चिताएं जलीं तो मुक्तिधाम में मौजूद लोग अपने आंसू नहीं रोक सके। पिता को मुखाग्नि देने वाली बेटी का चेहरा देखकर सभी गमगीन हो गए। कोंडावत गांव के एक कुएं में जहरीली से दम घुटने के कारण गुरुवार को 8 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव कुएं से बाहर निकाले जा सके। सभी 8 शवों को जिला अस्पताल ले जाया गया। रात 12 बजे तक डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमॉर्टम किया।

शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे सभी शवों को अलग-अलग वाहनों से गांव लाया गया। यहां अंतिम श्रद्धांजलि के बाद मुक्तिधाम ले जाया गया। अंतिम संस्कार में आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए। प्रशासन ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। एसडीएम बजरंग बहादुर ने कहा कि कुएं को तोड़कर मुरुम से भरा जाएगा। गुरुवार शाम छैगांवमाखन ग्राम पंचायत के कोंडावत गांव में गणगौर विसर्जन के लिए अर्जुन पटेल सफाई करने कुएं में उतरा था। वह जहरीली गैस के कारण बेसुध होकर कुएं में जमा दलदल में डूबने लगा। उसे बचाने के चक्कर में एक के बाद एक 7 और लोग कुएं में उतरे। ये सब भी जहरीली गैस के कारण दम घुटने से डूब गए और इनकी जान चली गई। एसडीएम बजरंग बहादुर ने कोंडावत गांव पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया- कल ही मशीन से कुएं को तोड़कर मुरुम का भराव किया जाएगा।

वक्फ बिल का विरोध

6 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ी

● बोले-मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा, बिहार में लगा चुनावी झटका

पटना (एजेंसी)। जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। इसके बाद से सीएम नीतिश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो गई है। एक के बाद मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जारी है। अब तक बिल को समर्थन देने से नाराज 6 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें पूर्व प्रदेश सचिव एम. राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सिए मो. तबरेज सिद्दीकी अलीग, भोजपुर से पार्टी सदस्य मो. दिलशान राईन और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल पर समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि, पार्टी ने दावों को खारिज किया है। वहीं, जदयू का कहना है कि राजद नेताओं ने मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। अनवर हुसैन, जिन्हें कबाब मंत्री के रूप में जाना जाता है, नामांकन के लिए संपत्ति के सौदे में शामिल थे। हालांकि, नीतिश कुमार हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रहे हैं। सीएम नीतिश हैं तो अल्पसंख्यक महफूज हैं। इधर, बिल पर जदयू के समर्थन को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि- नीतिश कुमार सेक्युलर थे, हैं और रहेंगे।

राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से लगा झटका

● 200 रुपए जुर्माना-समन रद्द करने की मांग खारिज

लखनऊ (एजेंसी)। राहुल गांधी की याचिका लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने वीर सावरकर मानहानि मामले में लखनऊ की सेशन कोर्ट के समन आदेश और 200 रुपए जुर्माने को लेकर हाईकोर्ट में 2 अप्रैल को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें अल्टरनेट रेमेडी (वैकल्पिक उपाय) अपनाने का सुझाव देते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट जाने को कहा है। दरअसल, 3 मार्च को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर राहुल गांधी पर 200 रुपए जुर्माना लगाया था। चेतावनी दी थी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों, अगर वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने बताया - 12 दिसंबर, 2024 को धारा 153 ए और 505 बीएनपी के तहत लखनऊ की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। 3 मार्च को कोर्ट ने भी 200 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने हमारी मांग खारिज कर दी। अब हम एक और याचिका दाखिल करेंगे। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। शिकायतकर्ता ने कहा- यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे। सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस चल रहा है।

कुएं से निकले हैंड ग्रेनेड और कारतूस के खोखे: सेना से जुड़े घातक हथियार मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस और आर्मी

जबलपुर। शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक पुराने कुएं की सफाई के दौरान हैंड ग्रेनेड और दर्जनों कारतूस के खोखे बरामद किए गए। यह घटना रांझी क्षेत्र के आमा नाला इलाके की है, जो भारतीय सेना की गतिविधियों और आयुध निर्माण इकाइयों से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। हथियारों के मिलने के बाद मौके पर पुलिस और सेना के अधिकारी पहुंच चुके हैं और मामले की गहराई से जांच शुरू हो गई है। गर्मी को देखते हुए नगर निगम की ओर से पुराने कुओं की सफाई का काम चल रहा था। जब सफाईकर्मी आमा नाला इलाके में एक कुएं की सफाई कर रहे थे, तभी एक के बाद एक हैंड ग्रेनेड और कारतूस के खोखे मिलने लगे।

कर्मचारी काम छोड़कर भाग खड़े हुए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल ने इलाके को घेर लिया और बम स्क्वॉड को भी बुला लिया गया।

प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि बरामद हथियार भारतीय सेना से जुड़े हो सकते हैं। ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया और आसपास मौजूद अन्य रक्षा संस्थानों से इनका कनेक्शन होने की संभावना जताई जा रही है। रांझी-खमरिया बेल्ट भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का केंद्र रहा है। ऐसे में इन हथियारों का यहां पहुंचना कई सवालों को जन्म देता है। घटनास्थल पर बम निरोधक दस्ते और सेना की इंटेलिजेंस यूनिट भी पहुंच गई है। अब यह जांच की जा रही है कि ये हथियार किस अवधि के हैं, किसने और क्यों इन्हें कुएं में छिपाया, और क्या ये अब भी सक्रिय हैं या निष्क्रिय। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की निगरानी तेज कर दी है। पूरे घटनाक्रम ने यह आशंका भी खड़ी कर दी है कि कहीं यह किसी पुराने सैन्य हथियारों की अवैध डंपिंग का मामला तो नहीं? विशेषज्ञों के अनुसार, आमतौर पर निष्क्रिय हो चुके हथियारों को निष्पादन प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ये वस्तुएं खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर पाई जा रही हैं, तो यह एक बड़ी लापरवाही है और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। पुलिस और जिला प्रशासन ने कुएं के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया है। फिलहाल हथियारों को सुरक्षित कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है और वे जानना चाहते हैं कि आखिर इतने सालों तक यह खतरनाक सामग्री सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे छिपी रही?

राजेंद्र नगर में स्टेडियम का भूमिपूजन

खेल मंत्री विश्वास सारंग बोले- हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा आधुनिक खेल परिसर

भोपाल (नप्र)। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के वार्ड 37, राजेंद्र नगर में नवीन स्टेडियम के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा।

मंत्री सारंग ने कहा कि, खेल और शारीरिक गतिविधियां युवाओं के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के नागरिकों को व्यायाम की सुविधा के साथ ही युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेल संचालक राकेश गुप्ता, संयुक्त संचालक बी.एस. यादव, खेल प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंत्री विश्वास सारंग ने राजेंद्र नगर में नवीन स्टेडियम के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। मंत्री सारंग ने कहा कि, यह स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात है। यहां विभिन्न खेलों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में क्षेत्र में खेल मैदानों का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही, क्लस्टर बनाकर नए खिलाड़ियों के निर्माण का प्रयास किया जाएगा।

स्टेडियम में दर्शकों के लिए विभिन्न सुविधाएं- मंत्री सारंग ने जानकारी दी कि स्टेडियम का निर्माण लगभग 8,000 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें से लगभग 4,000 वर्गमीटर में खेल मैदान विकसित होगा। यह स्टेडियम खिलाड़ियों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, और मल्टीपरपज हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खेल गतिविधियों के अलावा, यहां सांस्कृतिक एवं खेल आयोजनों के लिए मंच (स्टेज) भी बनाया जाएगा।

दो चरणों में होगा निर्माण

प्रथम चरण में फुटबॉल और अन्य खेल मैदानों का विकास, वॉलीबॉल कोर्ट, मैदान सुरक्षा दीवार, भव्य प्रवेश द्वार, हाई मास्ट प्रकाश व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए डग हाउस, जनसुविधा केंद्र, पाथवे (सुबह/शाम की सैर हेतु) और स्टेज उन्नयन का कार्य किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने सिस्टम पर उठाए सवाल: गुना CMHO नहीं दे पाए रिकॉर्ड, अब डायरेक्टर हेल्थ से मांगा जवाब

15 साल से लंबित प्रमोशन विवाद में हाईकोर्ट सख्त, 8 अप्रैल को अगली सुनवाई

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक पुराने सेवा विवाद में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने गुना के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (ष्ट्रस्वाह्र) द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत न किए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर डॉ. मल्लिका निगम नागर से सीधे जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जवाब पेश नहीं किया गया, तो डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता है। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को तय की गई है। यह मामला स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त बीपी शर्मा से जुड़ा है, जिन्होंने 2009 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सेवा काल के दौरान उनके जूनियर बीएन शर्मा को उनसे पहले प्रमोशन दे दिया गया, जबकि वे वरिष्ठ थे। उन्होंने कोर्ट से पदोन्नति और अन्य लाभों की मांग की थी।

रिकॉर्ड नहीं मिलने से भड़का कोर्ट

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में गुना के ष्ट्रस्वाह्र को रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए थे। ताजा सुनवाई में अधिकारी ने बताया कि बीएन शर्मा रिटायरमेंट के समय सागर में पदस्थ थे और उनका प्रमोशन आदेश भोपाल स्थित स्वास्थ्य निदेशालय से जारी हुआ था। उन्होंने भोपाल और सागर दोनों जगह रिकॉर्ड की तलाश की, लेकिन कोई सूचना नहीं मिल सकी। इस पर नाराज होते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ष्ट्रस्वाह्र इस रिकॉर्ड को ढूंढ़ने में असमर्थ हैं, इसलिए अब इस मामले की जिम्मेदारी डायरेक्टर हेल्थ को सौंपी जा रही है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी- कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई में भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो डायरेक्टर हेल्थ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। कोर्ट का यह रुख राज्य के स्वास्थ्य विभाग में चल रही प्रशासनिक उदासीनता और रिकॉर्ड प्रबंधन की खराब स्थिति पर एक बड़ा सवालिया निशान है।

'लोकतंत्र के मंदिर में ऐतिहासिक निर्णय': प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुस्लिम समाज को मिला नया अधिकार, पारदर्शिता और सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम: मुख्यमंत्री

भोपाल। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे 'लोकतंत्र के मंदिर में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय' करार देते हुए देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को मीडिया से बातचीत में कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय, खासकर गरीब मुसलमानों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक निर्णायक कदम है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं और वक्फ संशोधन बिल इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ÷यह कानून मुसलमानों के हितों को सुरक्षित करने, महिलाओं को सशक्त करने और वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है।÷

विपक्ष पर सीधा निशाना

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ÷कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करती हैं, उनके हित में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाती।÷ उन्होंने कहा कि इस विधेयक का स्वागत देश के गरीब मुसलमानों ने खुले दिल से किया है, जिससे विपक्ष की सियासी असलियत उजागर हो गई है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, पारदर्शी प्रबंधन और अवैध कब्जों पर रोक लगाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा। इससे राज्यों के वक्फ बोर्डों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और गरीब मुस्लिम समाज को उसका उचित हक मिलेगा। उन्होंने कहा, ÷यह कानून मुस्लिम महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि यह उन्हें संपत्ति, संरक्षण और न्याय की दिशा में मजबूती से खड़ा करेगा।÷ 'विकसित भारत' की दिशा में एक निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा।

खेत जा रहे किसान परिवार पर मधुमक्खियों का कहर: 7 लोग घायल, किसान और पत्नी की हालत गंभीर

पन्ना। जिले में एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना में मधुमक्खियों के झुंड ने खेत की ओर जा रहे किसान और उसके पूरे परिवार पर हमला कर दिया। घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कुल सात लोग घायल हुए हैं। इनमें किसान प्रेमसिंह यादव (60) और उनकी पत्नी गुड्डी यादव की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना मनकी कटारिया गांव की है। जानकारी के अनुसार, प्रेमसिंह यादव अपने परिजनों के साथ खेत जा रहे थे। जैसे ही वे घर से निकले, पास के एक पेड़ पर बैठे मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक धावा बोल दिया। अचानक हुए हमले से भगदड़ मच गई और सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए।

एम्बुलेंस से पहुंचे अस्पताल, दो की हालत गंभीर

स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह घायलों को बचाया गया और 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। ड्यूटी डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी के अनुसार, सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया है और फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन प्रेमसिंह और उनकी पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले इतना भयानक मधुमक्खियों का हमला कभी नहीं देखा। आशंका जताई जा रही है कि किसी तरह मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया गया, जिससे वे आक्रामक हो गईं और यह हमला किया।

रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार

रणजीत टाइम्स
इंदौर, शनिवार 5 अप्रैल 2025
03
DIGITAL EDITION

जंजीरवाला चौराहे से ट्रैफिक डायवर्ट, लेकिन सड़क पर अतिक्रमण और ठेलों ने बढ़ाया जाम, नेहरू नगर में रोजाना जाम की भीषण स्थिति

इंदौर। मालवा मिल से पाटनीपुरा चौराहे के बीच बनाए जा रहे नए पुल के कारण ट्रैफिक को डायवर्ट तो कर दिया गया, लेकिन वैकल्पिक मार्गों पर व्यवस्थाओं की भारी कमी अब लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। नेहरू नगर रोड नंबर 9 पर कब्जे, ठेले, बेतरतीब वाहन पार्किंग और ट्रैफिक पुलिस की गैरमौजूदगी के कारण हर दिन पिक आवर में वाहनों की कतारें लग रही हैं। जंजीरवाला चौराहे से आगे का रास्ता अब वाहन चालकों के लिए जाम और झुंझलाहट का केंद्र बन गया है। नगर निगम द्वारा फिलहाल पुराने पुल को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया है, जिसके चलते पूरा ट्रैफिक परदेशीपुरा और नेहरू नगर के रास्ते डायवर्ट कर दिया गया है। मालवा मिल से पाटनीपुरा की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग पर जहां पहले सुगम यातायात था, वहीं अब जंजीरवाला चौराहे से आगे निकलने पर गारबेज ट्रांसफर स्टेशन के पास बेतरतीब पार्किंग और फुटपाथ तक कब्जे ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अटल द्वार तक का पूरा रास्ता अब हर सुबह और शाम वाहनों के रेंगते काफिलों का दृश्य बन गया है।

नेहरू नगर में जिस वैकल्पिक मार्ग से ट्रैफिक निकाला जा रहा है, वहां की सड़कों पर आधे से ज्यादा हिस्से पर दोनों ओर अतिक्रमण है। दुकानदारों, गुमटियों और ठेले वालों ने सड़क को संकुचित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय सड़क किनारे चाट चौपाटी सज जाती है जिससे जाम और भी गहरा हो जाता है। नेहरू नगर से विकास नगर मोड़ तक का रास्ता अब जाम का स्थायी इलाका बन चुका है। हालात यह हैं कि गाड़ियां गलियों से निकलने की कोशिश में और भी बुरी तरह फंस रही हैं।

नगर निगम द्वारा अमर टेकरी और न्यू पलासिया को जोड़ने के लिए जो नया पुल बनाया गया था, वह भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। इस पुल पर अब गुमटियां सज चुकी हैं और तीन बड़े गाड़ी वाशिंग सेंटर की गाड़ियां पुल पर ही खड़ी रहती हैं। इससे यहां पर एक नया बॉटलनेक बन गया है, जहां से निकल पाना मुश्किल हो गया है। निगम की इस लापरवाही से साफ है कि वैकल्पिक मार्ग पर कोई प्रभावी निरीक्षण नहीं किया गया। चार दिन बीत जाने के बाद भी न तो निगम का कोई अधिकारी इन इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचा और न ही यातायात पुलिस की कोई विशेष तैनाती की गई। नतीजा यह है कि आम लोगों को हर दिन घंटों तक जाम से जूझना पड़ रहा है। नगर निगम और ट्रैफिक विभाग की इस लचर व्यवस्था से लोगों में नाराजगी है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिना पूरी तैयारी के इतना बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन कर देना सही था।

मनोरंजन का मंच बना सदनः 'फेकू-पप्पू' से लेकर 'जन्नत की हूर' तक, शेरो-शायरी और तंज में उलझे पार्षद, जनता ने उठाए सवाल

इंदौर। नगर निगम का बजट सत्र जिस पर शहरवासियों को उम्मीद थी कि विकास योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी, वह एक बार फिर हंगामे और हास्य का मंच बनकर रह गया। 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट पर सार्थक विमर्श के बजाय पार्षद आपसी नोकझोंक, तंज, शेरो-शायरी और विवादास्पद शब्दों में ही उलझे रहे। सदन की कार्यवाही के दौरान 'फेकू', 'पप्पू', 'कसाब', 'जन्नत की हूर', 'राम मंदिर', 'कर्बला की जमीन', 'जुम्मे की नमाज' और 'नवरात्रि की पूजा' जैसे असंवेदनशील और भटकाऊ शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ। कुछ पार्षदों ने अमिताभ बच्चन की शायरी तक का सहारा लिया। जनता की अपेक्षा थी कि विपक्ष शहर की समस्याएं उठाएगा, लेकिन जब डॉग बाइट और श्वान नसबंदी जैसे मुद्दों

पर चर्चा शुरू हुई, तो विपक्ष ठोस सुझाव नहीं दे सका। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्वयं खड़े होकर व्यवहारिक सुझाव मांगे, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया।

सदन में उस वक्त और बवाल मच गया, जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की गई। विपक्षी पार्षदों ने इसका विरोध करते हुए जोरदार हंगामा किया। करीब दो घंटे तक शोर-शराबे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। लंच ब्रेक के दौरान वही पार्षद जो थोड़ी देर पहले एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे थे, आपस में हंसी-मज़ाक करते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग सवाल उठा रहे हैं – क्या इसी दिन के लिए पार्षद चुने गए थे? जब जनता उम्मीद लगाए बैठे हो कि शहर की बेहतरी के लिए काम होगा, तब सदन का ऐसा रवैया लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। जनता का कहना है कि जब गंभीर विषयों पर भी मजाक बनाया जाए, तो फिर सवाल और तंज दोनों स्वाभाविक हैं।

इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, पत्नी की मौत, पति गंभीर

खंडवा। मध्यप्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला खंडवा जिले के मोरटक्का ब्रिज का है, जहां इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की तड़प-तड़प कर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक, हादसा मोरटक्का में नर्मदा नदी पर बने ब्रिज पर हुआ। सुखदेव और उनकी पत्नी खरगोन से इंदौर की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। दोनों दूर जा गिरे, और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज

से पहले ही पत्नी ने दम तोड़ दिया। सुखदेव को बड़वाह के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोरटक्का ब्रिज पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद न तो ट्रैफिक कंट्रोल के उपाय किए गए हैं और न ही स्पीड कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है। हादसे के बाद क्षेत्र में आक्रोश है और लोग प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

नगर निगम में कोर्ट की कार्रवाई से हड़कंप, आयुक्त की गाड़ी और ऑफिस फर्नीचर जब्त

इंदौर। नगर निगम मुख्यालय में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब कोर्ट के आदेश पर जिला अदालत की टीम पुलिस के साथ निगम कार्यालय पहुंची और आयुक्त समेत अधिकारियों की गाड़ियां और कार्यालय का साजो-सामान जब्त कर लिया। कार्रवाई इंदौर एडीजे कोर्ट के आदेश पर की गई जिसमें नगर निगम पर 2.25 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि न चुकाने का मामला था। यह मामला गौरी शंकर बनाम नगर निगम के तहत सामने आया है जिसमें सड़क चौड़ीकरण के दौरान एक व्यक्ति के मकान टूटने पर उसे मुआवजा देना था लेकिन नगर निगम ने उसे अब तक भुगतान नहीं किया था। कोर्ट द्वारा पहले ही इस मामले में निर्देश दिए गए थे कि भुगतान तत्काल किया जाए लेकिन निगम ने आदेश की अनदेखी की जिसके चलते नजारत विभाग की टीम कुर्की का आदेश लेकर पहुंची, टीम ने नगर निगम आयुक्त की कार, अन्य अधिकारियों के वाहन, ऑफिस में रखी कुर्सियां, टेबल, अलमारियां, पंखे, एसी और सोफे तक जब्त कर लिए। कुर्की

की यह कार्रवाई तब हुई जब निगम कार्यालय के दूसरे हिस्से में नगर निगम का बजट सम्मेलन चल रहा था जिसमें महापौर, निगम आयुक्त और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही जब्ती की कार्रवाई की खबर फैली निगम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कार्यालय में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। यह मामला नगर निगम की प्रशासनिक लापरवाही और कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का जीवंत उदाहरण बन गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी। नगर निगम जैसे संस्थान की इस स्तर की उदासीनता से न केवल न्याय व्यवस्था की अवमानना हुई बल्कि आम जनता के बीच यह संदेश गया कि सरकारी सिस्टम कितनी गंभीर चूक कर सकता है।

आयुष्मान योजना में घोटाले का बड़ा खुलासा: ट्रामा सेंटर में कमीशन के खेल का वीडियो वायरल, अस्पताल पर जांच की तलवार लटकी

इंदौर। बहुचर्चित आयुष्मान भारत योजना अब गंभीर आरोपों के घेरे में है। इंदौर के ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस योजना के तहत कमीशनखोरी और फर्जी रेफर का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो में अस्पताल का डॉक्टर एक एंबुलेंस ड्राइवर से मरीज लाने के बदले खुलकर कमीशन देने की बात करता दिख रहा है। कैसे सरकारी अस्पतालों से मरीजों को निजी अस्पताल में रेफर किया जा रहा है और बदले में कमीशन का खेल चल रहा है। इस खुलासे के बाद भोपाल स्वास्थ्य विभाग ने हरकत में आते हुए अस्पताल को नोटिस जारी किया है, लेकिन इंदौर का स्वास्थ्य अमला अब तक चुप्पी साधे हुए है। सूत्रों की मानें तो अगर जांच में गड़बड़ी साबित होती है, तो अस्पताल को सील किया जा सकता है। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिलहाल कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या किसी रसूखदार का संरक्षण अस्पताल को मिल रहा है?

अस्पताल संचालक ने पल्ला झाड़ा, लेकिन सवाल बरकरार- अस्पताल के संचालक डॉ. कमल गहलोत ने सफाई देते हुए कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है, वह अस्पताल के किसी क्लास-3 कर्मचारी की निजी बातचीत है और उसका अस्पताल से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर रिसेप्शन से लेकर ओटी रूम तक पूरा स्टाफ इस सिस्टम का हिस्सा है, तो जवाबदेही किसकी होगी? खुलासा यहीं नहीं रुका। आयुष्मान कार्ड धारकों से मुफ्त इलाज के नाम पर मनमानी रकम वसूली जा रही है। कई मामलों में मरीजों से नकद भुगतान लिया गया, लेकिन कागजों में इलाज आयुष्मान योजना के तहत दिखाया गया। डॉ. तुलसी पटेल और राहुल चौधरी पर सीधे तौर पर कमीशन बांटने, सरकारी अस्पतालों से रेफर कराने और मरीजों का शोषण करने के आरोप हैं। यह मामला सिर्फ एक अस्पताल की अनियमितता नहीं, बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की साख पर सवाल है। अगर अब भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह घोटाले को खुली छूट देने जैसा होगा। आम लोगों की जिंदगी के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर अब सरकार और प्रशासन को जवाब देना ही होगा।

4 अप्रैल 2025

अलविदा 'भारत कुमार'

भावभीनी श्रद्धांजलि

भारतीय सिनेमा ने अपना एक अमूल्य रत्न खो दिया। मनोज कुमार जी – जिन्हें पूरी दुनिया 'भारत कुमार' के नाम से जानती थी – का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

»»जन्मः 24 जुलाई 1937

»»निधनः 04 अप्रैल 2025

उनकी फिल्मों ने भारत को नई नज़रों से देखने की प्रेरणा दी – उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति जैसी देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों ने उन्हें हर दिल में अमर कर दिया। "देशभक्ति को सिल्वर स्क्रीन पर जीवंत करने वाले कलाकार को शत-शत नमन।"

युवा मोर्चा ने किया महापौर पुष्यमित्र भार्गव का अभिनंदन

नगर निगम बजट में युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की स्वीकृति को लेकर किया अभिनंदन

इंदौर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष श्री सौगात मिश्रा ने बताया कि इंदौर के मान. महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी द्वारा युवा मोर्चा के आग्रह पर प्रस्तुत बजट में युवाओं के प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा हेतु स्वीकृति दी जाने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत ही हर्ष है श्री मिश्रा ने कहा कि हमारे महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव युवा है और वे युवाओं के लिए नवाचार करते आ रहे हैं महापौर जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा हेतु स्वीकृति दी जाने से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न है इस हेतु सभी ने मिलकर महापौर जी का अभिनंदन किया उन्हें धन्यवाद दिया है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा

के नगर अध्यक्ष श्री सौगात मिश्रा, नगर मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी,सह मीडिया प्रभारी नितिन द्विवेदी, रजत शर्मा, अजय अग्निहोत्री,विकास यादव,आवेश राठौर, संतोष रघुवंशी,राहुल अवस्थी,नवदीप चुटेले सहीत बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों ने डिपॉजिट रेट्स घटाने शुरू किए

एचडीएफसी, यस बैंक, बंधन और बजाज फाइनेंस ने घटा दिए हैं डिपॉजिट रेट्स

- आरबीआई की एमपीसी इस हफ्ते की बैठक में रेपो रेट में और कटौती कर सकती है

नईदिल्ली, एजेंसी। बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों ने डिपॉजिट रेट्स घटाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है साथ ही लिक्विडिटी (रुपये की उपलब्धता) में भी सुधार होने की बात कही जा रही है। एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक और एनबीएफसी बजाज फाइनेंस ने इस हफ्ते डिपॉजिट रेट्स घटा दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे आने वाले दिनों में लोन (उधार) पर ब्याज दरें भी कम होंगी और आरबीआई की नीतियों का असर आम लोगों तक जल्दी पहुंचेगा। आरबीआई ने जनवरी से सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे हैं। मंगलवार को उसने और 80,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदने का ऐलान किया। यानी आरबीआई बाजार में और पैसा डाल रही है ताकि ब्याज दरें कम हो।

इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, इस साल फरवरी में सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कमी की थी उम्मीद है कि एमपीसी की अगली मीटिंग में रीपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती हो सकती है। अधिकतर बैंकों

से इस तिमाही में डिपॉजिट रेट्स कम करने की उम्मीद है। उन्होंने पहले ही येपो रेट से जुड़े एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट के आधार पर डिपॉजिट रेट्स घटा दिए हैं लेकिन बैंकरों का कहना है कि वो अभी अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के आधार पर लोन की दरें तुरंत नहीं घटाएंगे। डिपोजिट रेट्स में कटौती से एमसीएलआर में कमी का रास्ता साफ होता है। एचडीएफसी बैंक, येस बैंक और बजाज फाइनैंस ने डिपोजिट रेट्स 0.25-0.40 प्रतिशत तक घटा दिए हैं। बंधन बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दरों में आधी तक कटौती की है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बैंक ऐसे वक्त में ब्याज दरें कम कर रहे हैजब सरकार ने अप्रैल-जून के लिए अपनी सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की दरें जस की तस रखी हैं। इनमें आरबीआई बॉन्ड्स और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पर ज्यादा से ज्यादा 8.2 प्रतिशत ब्याज मिलता है Money Honey फाइनैंशल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप भैया कहते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट करने वालों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चार से पांच साल की लंबी अवधि के लिए ज्यादा ब्याज दरों पर पैसा लगा देना चाहिए। फाइनैंशल प्लानर्स बताते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट (स्र इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये समझने में आसान होते हैं और नियमित रूप से पैसा मिलता रहता है। यह बाजार की स्थिति पर निर्भर नहीं होता। ये प्रोडक्ट्स रिटायर लोगों या उन निवेशकों को पसंद आते हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं और बिना किसी अनिश्चितता के काम को सरल रखना चाहते हैं। इसके मुकाबले, डेट फंड्स पर रिटर्न तय नहीं होता और चुने हुए फंड और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के आधार पर ये अस्थिर हो सकते हैं। ज्यादा ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के दौरान मार्केट टू मार्केट लाभ या नुकसान हो सकता है। ये कटौती खास तौर पर उन स्पेशल डिपॉजिट्स पर केंद्रित है जो सीमित समय (31 मार्च तक) के लिए ज्यादा ब्याज दरों पर शुरू की गई थीं।

धार्मिक स्थानों की गरिमा बनाए रखने का प्रयास है, शराब बंदी

- सीएम ने पीतांबरा पीठ में किया पूजन, आभार सभा को भी किया संबोधित
- बोले-शराब की लत घर बर्बाद करती है

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए धार्मिक स्थानों की पवित्र गरिमा को बनाए रखने के लिये शराब बंदी का प्रयास किया है, इसके लिये शासन ने भले ही राजस्व की हानि स्वीकार की है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी का निर्णय इसी दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के 17 से अधिक शहरों में शराब बंदी की घोषणा कर उसे क्रियान्वित भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल से दतिया रवाना होने से पहले मीडिया को जारी संदेश

में यह विचार रखे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सुशासन की ओर अग्रसर हो रही हमारी सरकार पर जनता की सेवा और कल्याण के लिए पीताम्बरा माई अपना आशीर्वाद बनाए रखें-यही प्रार्थना है। प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। दतिया स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद सभा में उन्होंने नशे से होने वाले दुष्परिणामों पर चिंता जताते हुए कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश दिए। सीएम सुबह करीब 11.40 बजे दतिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम यादव ने भाजपा के मूल सिद्धांत वसुधैव कुटुम्बकम का उल्लेख करते हुए पार्टी की कार्य संस्कृति पर भी प्रकाश डाला।

माहेश्वरी समाज

महिला मंडल ने निकाला गणगौर का बनोरा

नागदा । रेल्वे स्टेशन परिसर स्तिथ शिव मन्दिर परिसर से माहेश्वरी समाज महिला मंडल द्वारा अध्यक्ष ज्योति मोहता , के नेतृत्व में गणगौर का बनोरा निकाला गया , गणगौर शोभायात्रा का पुष्प बरसाकर जगह जगह स्वागत किया गया।

जज वर्मा मामले से जजों की नियुक्ति में केंद्र को मिला मौका

स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अर्थात किसी भी जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बाद गंभीर किस्म के आरोपों के बाद किसी भी जज को हटाया जाना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ हाईकोर्ट के जजों की तबादले की शक्ति है। हटाने का काम संसद का है। संसद में राजनीतिक दल भी ऐसे मुद्दों पर बंटे नजर आते हैं। जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद न्यायिक नियुक्ति आयोग को बहाल करने की मांग बेशक की जा रही हो, किन्तु जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में महाभियोग के पारित नहीं होने के लिए राजनीतिक दल ही जिम्मेदार हैं। राजनीतिक दलों के अपने-अपने स्वार्थ निहित हैं। वर्मा प्रकरण की आड़ में केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति-तबादले में अपनी हिस्सेदारी चाहती है।

योगेंद्र योगी

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर मिले लाखों रुपए के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया है। केंद्र सरकार ने संसद में कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून पारित किया था। इस कानून के एक विवादास्पद प्रावधानों में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में भारत के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम जजों और केन्द्रीय कानून मंत्री के अलावा दो जानी मानी हस्तियों को शामिल करने की व्यवस्था थी। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून-एनजेएसी को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था।

जस्टिस वर्मा नोट प्रकरण के बाद न्यायिक नियुक्ति आयोग फिर से लागू करने की संभावना के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की उम्मीद फिर से पैदा हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में राजनीतिक दलों से कहा कि उन्हें जजों की तरफ से जजों की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक तंत्र के बारे में सोचना चाहिए। धनखड़ ने कानून को रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले को गलत बताया। उन्होंने वर्ष 2014 में सर्वसम्मति से बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को दूरदर्शी कदम बताया। इसका उद्देश्य एससी और एचसी के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एकाधिकार को समाप्त करना था। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय सहित विपक्षी नेताओं ने सरकार से उन कदमों की रूपरेखा तैयार करने को कहा है जो वह उठाना चाहती है।

जज कैशकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की फजीहत दो कारणों से हो रही है। न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने और जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने से। आयोग को रद्द करने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ द्वारा राजनीतिक दलों की बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयोग को निरस्त करने के फैसले की तीखी भर्त्सना की गई। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाइकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का विरोध किया है। एसोसिएशन ने हड़ताल के अलावा जस्टिस वर्मा की कोर्ट के बहिष्कार की चेतावनी दी है। जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर से उंगलियां उठने लगी हैं। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने और इनमें परिवारवाद को वरीयता दिए जाने को ÷अंकल जज सिंड्रोम÷ कहते हैं। जब जज बनाने के लिए अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो किसी भी स्तर पर किसी से कोई राय नहीं ली जाती। ऐसे में जिन लोगों का नाम प्रस्तावित किया जाता है, उनमें से कई पूर्व न्यायाधीशों के परिवार से होते हैं या उनके संबंधी होते हैं। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों में %अंकल जजों% की

नियुक्ति के मामले का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन जजों के परिजन किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, उन्हें उसी उच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। विवादों में घिरे जस्टिस वर्मा का अकेला मामला नहीं है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष परेशानी खड़ी हुई है। पूर्व में हाईकोर्ट के जजों खिलाफ इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी जानकारी मांगी वहीं, संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग ने जोर पकड़ा। जस्टिस वी. रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 1993 में लोकसभा में लाया गया था। लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया था क्योंकि उसे जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं हो सका। जस्टिस रामास्वामी 1990 में पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे तब उन पर आधिकारिक तौर पर अलॉट किए गए घर पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा था।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन देश के दूसरे जज थे जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा था। उनके खिलाफ 2011 में राज्य सभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। जस्टिस सौमित्र सेन ने महाभियोग चलाए जाने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को अपना इस्तीफा भेज दिया था। वह पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिन पर उच्च सदन द्वारा कदाचार के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। वर्ष 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सांसदों ने अपने प्रस्ताव में अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ उनके अपशब्द कहे जाने पर आपत्ति जताई थी। उस समय उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी के पास महाभियोग का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद जस्टिस पारदीवाला ने अपने फैसले से वह शब्द हटा लिए थे। भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों पर सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की गई थी। लेकिन सुनवाई के कुछ दिनों पहले ही दिनाकरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दिनाकरन पर जमीन पर कब्जा करने और आय से अधिक संपत्ति के मामले थे। इसके अलावा 2017 में राज्यसभा सांसदों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। मार्च 2018 में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। उन पर विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, लेकिन राज्यसभा के तत्कालीन सभापति ने उसे खारिज कर दिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. गंगले के खिलाफ भी महाभियोग की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन पूरी नहीं हो पायी।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अर्थात किसी भी जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बाद गंभीर किस्म के आरोपों के बाद किसी भी जज को हटाया जाना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ हाईकोर्ट के जजों की तबादले की शक्ति है। हटाने का काम संसद का है। संसद में राजनीतिक दल भी ऐसे मुद्दों पर बंटे नजर आते हैं। जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद न्यायिक नियुक्ति आयोग को बहाल करने की मांग बेशक की जा रही हो, किन्तु जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में महाभियोग के पारित नहीं होने के लिए राजनीतिक दल ही जिम्मेदार हैं। राजनीतिक दलों के अपने-अपने स्वार्थ निहित हैं। वर्मा प्रकरण की आड़ में केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति-तबादले में अपनी हिस्सेदारी चाहती है। ऐसा नहीं है कि जजों की नियुक्ति में लगे भाई-भतीजावाद के आरोप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही लगे हों, यदि राजनीतिक दलों को आयोग की बहाली के बाद ऐसा करने का मौका मिल गया तो वे उससे दो कदम आगे जाएंगे। इसके बाद न्यायिक शुचिता का अभी जो हाल है, उसे और भी ज्यादा खराब होने से कोई रोक नहीं सकता।

"मध्यप्रदेश पुलिस में डिजिटलीकरण की नई पहल

बड़वानी 1

मध्यप्रदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की अध्यक्षता में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय बड़वानी के सभा गृह में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य सीसीटीएनएस और ई-ऑफिस के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाना था। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक मकवाना ने मध्यप्रदेश पुलिस के कार्यों को डिजिटली सशक्त बनाने हेतु ई-ऑफिस को सभी कार्यालयों में लागू करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत अब सभी कार्यालयीन पत्राचार केवल ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा, जिससे फाइलों का आदान-प्रदान शीघ्र और सुगमता से संभव होगा। इस कदम से कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि होगी। साथ ही, सीसीटीएनएस सॉफ़्टवेयर के माध्यम से होने वाले कार्यों की भी समीक्षा की गई, जैसे- प्राथमिकी पंजीकरण, चालान, ई-विवेचना, ई-एफआईआर, ई-साक्ष्य, जीरो एफआईआर, ई-समन, वारंट आदि। पुलिस महानिदेशक ने इन सभी कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन और सही निगरानी की दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वीडियो कांनफ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई इस मीटिंग में पुलिस अधीक्षक बड़वानी जगदीश डावर, सीसीटीएनएस प्रभारी महेन्द्र सिंह, डीसीबी शाखा प्रभारी असद खान, मुख्य लिपिक मुकेश डावर सहित समस्त शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। यह बैठक मध्यप्रदेश पुलिस के कार्यालयीन कार्यों में डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिससे सभी कार्यों में गति और पारदर्शिता आएगी।

इंडस्ट्रीयल डिजाइनिंग में मास्टर्स करें, अच्छी रहेगी करियर ग्रोथ

आज जहां भी नजर दौड़ाए, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की एक से बढ़कर एक मिसालें देखने को मिल जाती है। फिर चाहे वह कोई गैजेट हो, डिजाइनर वॉच या होम अप्लायंस। ऐसे में कई बार सोचने में आता है कि इन्हें डिजाइन कौन करता है, इनका क्रिएटर ये काम प्रोडक्ट डिजाइर्स करते हैं जो कि इमेजिनेटिव पॉवर और एस्थेटिक सेंस की बदौलत टेक्टिनकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इंजीनियरिंग का एडवांस ब्रांच है प्रोडक्ट डिजाइनिंग जिसमें इन दिनों युवाओं का अच्छा रुझान देखा जा रहा है।

स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बच्चों के खिलौने से लेकर ड्राइंग रूम के स्टाइलिश व स्मार्ट फर्नीचर्स तक आज जहां भी नजर दौड़ाए, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की एक से बढ़कर एक मिसालें देखने को मिल जाती है। फरि चाहे वह कोई गैजेट हो, डिजाइनर वॉच या होम अप्लायंस। ऐसे में कई बार सोचने में आता है कि इन्हें डिजाइन कौन करता है, इनका क्रिएटर ये काम प्रोडक्ट डिजाइर्स करते हैं जो कि इमेजिनेटिव पॉवर और एस्थेटिक सेंस की बदौलत टेक्टिनकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इंजीनियरिंग का एडवांस ब्रांच है प्रोडक्ट डिजाइनिंग जिसमें इन दिनों युवाओं का अच्छा रुझान देखा जा रहा है।

वर्क प्रोफाइल

प्रोडक्ट डिजाइनर्स कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए आर्टिकल्स, प्रोडक्ट्स, मटीरियल्स डिजाइन करते हैं। कोई भी चीज डिजाइन करने से पहले ये उसकी विजुअल अपील और प्रैक्टिकल यूज का पूरा ध्यान रखते हैं। एक प्रोडक्ट डिजाइन को कार, होम अप्लायंस, कम्प्यूटर, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑफसि या रिक्रिएशन इक्विपमेंट, खिलौने आदि कुछ भी डिजाइन करने पड़ सकते हैं। उन्हें मार्केट रिसर्चर्स, एडवरटाइजिंग टीम और प्रोडक्शन मैनेजस से इंटरेक्ट करने के अलावा ग्राफकि डिजाइनर्स के साथ काम करना होता है।

स्किल्स

प्रोडक्ट डिजाइनर को आर्टिस्टिक होने के साथ लॉजिकल थिंकर होना भी जरूरी है। आपके पास आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज होंगे तो अलग पहचान बना सकेंगे। इसी तरह ऑब्जर्वेशन स्किल और विजुअल इमेजिनेशन बेहतरीन होनी चाहिए। आपको ड्रांइंग के माध्यम से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन और मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता

अगर आपके पास आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में डिग्री होगी, तो आप आईआईटी से इंडस्ट्रीयल डिजाइनिंग में मास्टर्स कर सकते हैं। इससे करियर ग्रोथ अच्छी रहेगी। वैसे, साइंस स्ट्रीम से बारहवीं करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन या आईआईटी से इंडस्ट्रियल डिजाइन का कोर्स कर, प्रोडक्ट डिजाइनिंग की फील्ड में आ सकते हैं।

मार्केट में अवसर

मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के डिजाइन डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट डिजाइनर्स की अच्छी मांग होती है। आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइनर , वॉच डिजाइनर, फुटवियर डिजाइनर, डिजिटल डिजाइनर, आदि के रूप में करियर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टिंग फर्म्स में जॉब की जा सकती है।

प्रमुख संस्थान

- इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर, आईआईटी बॉम्बे
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद
- एमआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, पुणे
- सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, पुणे

टेक्सटाइल डिजाइनर्स के लिए बढ़ी करियर की संभावनाएं

आज भी कृषि के बाद लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल फील्ड में मिला हुआ है। देशवासियों की बढ़ती क्रय शक्ति तथा ब्रांडेड प्रोडक्ट के प्रति बढ़ता आकर्षण इस बात का संकेत है कि टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री में आगे भी तेजी बनी रहेगी। बीते एक दशक में रिटेल सेक्टर के विकास ने भी साबित कर दिखाया है कि उपभोक्ताओं की लाइफस्टाइल और शॉपिंग ट्रैंड्स बदल गए हैं। लोग फैशन और क्वॉलिटी प्रोडक्ट को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ने से इस सेक्टर को विकास करने का मौका मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय टेक्सटाइल बाजार करीब दोगुना हो जाएगा। यही कारण है कि युवाओं के लिए टेक्सटाइल के सभी सबसेक्टर्स – टेक्सटाइल्स एंड अपेरल, हैंडीक्राफ्ट, सोफिस्टिकेटेड मिल, हैंडलूम, जूट और सेरिकल्चर में काम की संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी। इसके अलावा, सरकार द्वारा इंडिया हैंडलूम प्रमोशन जैसी योजना शुरू किए जाने और इस सेक्टर में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से भी इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर रोजगार में लगातार इजाफा होता रहेगा।

काम के अवसर

देश में गारमेंट, फैशन, ज्वेलरी, लगेज, एक्सेसरी, होम फर्निशिंग व इंटीरियर टेक्सटाइल का बाजार दिनो-दिन बढ़ रहा है, जहां टेक्सटाइल डिजाइनर्स के लिए ढेर सारे नए अवसर मौजूद हैं। ऐसे प्रोफेशनल्स की विदेश के अलावा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, फैशन डिजाइनिंग एजेंसियों, एक्सपोर्ट हाउस और टेक्सटाइल रिटेल जैसी फील्ड में काफी मांग है। सरकार की मदद से चल रही खादी, जूट, सिल्क और क्राफ्ट जैसी संस्थाओं में भी डिजाइनिंग प्रोफेशनल्स के लिए अच्छे अवसर हैं। ऑटोमोटव टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक नया उभरता क्षेत्र है, जहां मोटर निर्माण कंपनियां अपनी कारों के इंटीरियर को अपीलिंग लुक देने के लिए ऐसे डिजाइनर्स की खूब सेवाएं ले रही हैं। इसके अलावा, अगर आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं, तो एग्रीकल्चर फील्ड में रेशम उत्पादन और कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए रिसर्चर की भूमिका अदा कर सकते हैं। युवा चाहें, तो डिजाइनिंग का काम पार्ट-टाइम कर सकते हैं। आप अपना खुद का बुटीक भी खोल सकते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों में भी क्रिएटिव लोगों को हायर किया जाता है। आप चाहें, तो ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए वेंडर भी बन सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता

टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिग्री, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के रूप में कई कोर्स आजकल संचालित हो रहे हैं। ये कोर्स आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अगर चाहें, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बीई या बीटेक कोर्स भी कर सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली

आईपीएल 2025:

हैदराबाद के जानी दुश्मन है वेंकटेश अय्यर

इन 5 स्लॉग ओवर्स में लगा दी लंका, जब-जब खेले तब-तब बजाया बैंड

नई दिल्ली, एजेंसी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच 3 अप्रैल को हुए मुकाबले में 15 ओवर का खेल हो चुका था. चक्रके वेंकटेश अय्यर 10 गेंदों पर 11 तो रिंकू सिंह 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेल रहे थे. कोलकाता की टीम का स्कोर हुआ था 122/4. इस स्कोर के बाद ही वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने ऐसा मोर्चा संभाला कि कोलकाता ने 20 ओवर्स में पूरे 200 रन बना डाले. इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भले ही चक्रके वैभव अरोड़ा रहे, पर कोलकाता के लिए मैच बनाने का काम प्रमुख तौर पर वेंकटेश अय्यर ने किया. वरना एक समय कोलकाता के लिए 200 का स्कोर दूर के ढोल की तरह था. वहीं आखिरी के 5 ओवर्स में बल्ले से अय्यर और रिंकू ने तबाही मचा दी. कोलकाता की पारी का 16वां ओवर एसआरएच के पेसर मोहम्मद शमी करने आए. इस ओवर में अय्यर और रिंकू ने मिलकर 12 रन बनाए. फिर 17वें ओवर हर्षल पटेल के हाथ में था , यहां 15 रन आए. 18वें ओवर में सिमरतजीत सिंह अय्यर और रिंकू के सामने पड़े तो फिर 17 रन आए. जब सभी गेंदबाज स्लॉग ओवर में पिट रहे थे तो 19 ओवर खुद कप्तान कमिंस लेकर आए. लेकिन कमिंस की रिंकू और अय्यर ने ऐसी खातिरदारी की उनके ओवर मं 21 रन कूट दिए. 20वां ओवर हर्षल पटेल ने फेंका, जहां कुल 13 रन आए. इस ओवर में तीसरी गेंद पर 29 गेंदों पर 60 रन की पारी खेलने के बाद वेंकटेश अय्यर आउट तो हो गए, लेकिन वो तब तक अपना काम कर चुके थे.

अय्यर से पहले अंगकृष रघुवंशी ने 32 रनों पर 50 रनों की पारी खेली. वहीं कोलकाता की ओर कप्तान अजिक्य रहाणे ने 38 तो रिंकू सिंह (32 नाबाद) ने भी सधी पारियां खेलीं. इस वजह से कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर्स में 200/6 का स्कोर बनाया. बाद में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम वैभव अरोड़ा के नेतृत्व में इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पर टूटी कि उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला. को मुकाबले में 80 रनों से हार मिली, जो उसकी रनों के लिहाज से आईपीएल में सबसे बड़ी हार रही. वहीं एसआरएच की इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार रही, वो केवल अपना पहला मुकाबला ही जीत सकी थी. सीईओ काव्या मारन की यह टीम अब प्वाइंट्स टेबल में सबसे फिर है. कोलकाता जीत के बाद प्वाइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर है.

आईपीएल में इस दशक में सबसे ज्यादा शतक जोस बटलर के नाम

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2025 का कारवां आगे बढ़ रहा है और एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले क्रिकेट फैंस को देखने को मिल रहे हैं। वैसे इस सीजन में 14 मैच खत्म होने तक सिर्फ एक शतक लगा है जो केकेआर के बल्लेबाज इशान किशन ने लगाया है। वैसे इस सीजन में और भी शतक देखने को मिलेंगे, लेकिन इस दशक में यानी साल 2020 से अब तक आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर जोस बटलर हैं। जोस बटलर इस सीजन में आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने अपनी टीम के लिए सीजन के तीसरे मैच में आरसीबी खिलाफ नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

जोस बटलर आईपीएल के कुछ बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं और वो विकेटकीपिंग भी करते हैं। बटलर का आईपीएल में रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। आईपीएल में वैसे तो सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली (8 शतक) के नाम पर दर्ज है और उसके बाद दूसरे नंबर पर जोस बटलर हैं जिन्होंने अब तक 7 शतक लगाए हैं, लेकिन इस दशक में यानी साल 2020 से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर की लिस्ट में बटलर पहले नंबर पर हैं। बटलर ने आईपीएल में अपने सारे शतक इस दशक में यानी साल 2020 से लगाए हैं। इस दशक में बलटर ने अब तक आईपीएल की 64 पारियों में सबसे ज्यादा 7 शतक लगाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं जिन्होंने 79 पारियों मे 4 शतक ठोके हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से केएल राहुल और विराट कोहली मौजूद हैं। कोहली ने इस दशक में आईपीएल में 78 पारियों में 3 शतक जबकि केएल राहुल ने 66 पारियों में कुल 3 शतक जड़े हैं।

आईपीएल में इस दशक में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर

7 - जोस बटलर (64 पारी)
4 - शुभमन गिल (79 पारी)
3 - केएल राहुल (66 पारी)
3 - विराट कोहली (78 पारी)

जीवन में अनुकूलता का अभिमान घातक है और यही पतन का कारण बनता है:आचार्य हितेशचंद्रसूरीश्वरजी

पेटलावद जीवन में यदि अनुकूल स्थिति आए तो अभिमान मत आने देना यह घातक होता है। किसी को रूप का, किसी को दौलत का तो किसी को ज्ञान का अभिमान होता है। आहार को पचाना सरल है किंतु ज्ञान को पचाना बहुत ही मुश्किल है। ज्ञान का अभिमान यदि आता है तो यह अभिमान पतन का कारण हो सकता है। मनुष्य यदि सरल एवं सहज बनकर जीयेगा तो वास्तविकता में जीवन जीने का आनंद आएगा। यह प्रेरक संदेश गच्छादिपति हितेशचंद्रसूरीश्वरजी महाराज साहब ने श्री राजेंद्रसुरीजी गुरु मंदिर में प्रवचन के दौरान फरमाए। गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य भव में आने के पूर्व हमारी आत्मा ने न जाने कितने परिभ्रमण किए है। और परिभ्रमण के इस दौर को सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह मन की परिणीति के माध्यम से होता है। जीवन में मोक्ष की चाहना लेकर चलने वाला, कर्म की निर्जरा कर सिद्ध सौंपान पाने वाला अपने मन की परिणीति बदल कर श्रेष्ठ बना लेता वह निश्चित रूप से कर्म रूपी विजेता को प्राप्त कर लेता है।

गुरुदेव ने आगे फरमाया कि यदि मन की परिणीति नहीं बदली तो हमारे जीवन में बंधन का रास्ता खुला रहता है। और यह दौर निरंतर चलता रहता है। आपने कहा कि एक सागर जिस प्रकार पवित्र नदी के जल के साथ महानगरों का गंदा जल भी अपने में समाहित कर लेता है वह किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है। इसी प्रकार यदि हमारे मन में कोई भेद नहीं होगा तो ही हमारे जीवन की सार्थकता है।

अनेक स्थानों पर गहुली कर अगवानी की

त्रिस्तुतीक श्री संघ पेटलावद के अध्यक्ष सागरमल सुराणा ने बताया कि गच्छादिपति आचार्य श्री हितेशचंद्र सुरिश्वरजी महाराज साहब आदि ठाना 3 का बामनिया रोड से पेटलावद नगर मे प्रवेश हुआ। नगर में कई स्थानों पर गुहली की गई। उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल को श्री सांचल सोनाणा तीर्थ धाम बामनिया पर श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ के भव्य जिनालय का निर्माण हेतु गच्छादिपति हितेशचंद्रसूरीश्वरजी व दिव्यचंद्रविजयजी, वैराग्यवशविजय आदि ठाणा-3 की पावन निश्रा में भूमिपूजन सम्पन्न हुआ। उसके पश्चात गुरुदेव विहार कर पेटलावद पधारे। धर्मसभा में प्रबोध मोदी ने गुरुदेव के आगमन को लेकर समग्र जैन समाज के संघों की ओर से हर्ष व्यक्त कर गुरु मंदिर पर नव निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस अवसर पर तेरापंथ सभा के अध्यक्ष नरेंद्र पालरेचा, महावीर समिति के अध्यक्ष संजय व्होरा (पप्पू भाई), अरिहंत युवा वाहिनी के अध्यक्ष पंकज पी पटवा, पूर्व अध्यक्ष चिंतन मंडलोई, संजय सुराणा, सुधीर छजलानी, मनोज ओरा, अनिल मेहता, पंकज जे पटवा, संजय मालवी, चेतन कटकानी, विजय भंडारी,दिलीप लोढ़ा,संजय भंडारी, अभिषेक पमपम पटवा, सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। इस के पूर्व समग्र जैन समाज की नवकारसी का आयोजन भी त्रिस्तुतीक श्री संघ द्वारा किया गया।

डीएनए रिपोर्ट पिता तय कर सकती है, सहमति का अभाव नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को किया बरी

नईदिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक अहम फैसला देते हुए 10 साल जेल की सजा पाने वाले दोषी को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से केवल पितृत्व साबित होता है, सहमति का अभाव साबित नहीं होता।

जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट से भले ही यह साबित हो गया कि महिला की कोख से जन्मे बच्चे का जैविक पिता आरोपी ही है, लेकिन अकेले गर्भावस्था दुष्कर्म का अपराध सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि यह भी न साबित किया जाए कि संबंध सहमति के बिना बनाया गया था।

हाईकोर्ट ने 20 मार्च को सुनाए गए अपने फैसले में कहा, डीएनए रिपोर्ट केवल पितृत्व को साबित करती है- यह सहमति के अभाव को न तो सिद्ध नहीं करती है और ना ही कर सकती है। यह एक स्थापित कानून है कि आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत अपराध की सिद्धि सहमति के अभाव पर निर्भर करती है। फैसले में कहा गया कि

घटना से जुड़ी परिस्थितियों ने अभियोजन पक्ष के मामले को 'अत्यधिक असंभव' बना दिया है।

जस्टिस महाजन ने फैसले में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया कि बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी से दर्ज कराई गई एफआईआर 'सामाजिक दबाव का नतीजा' हो सकती है।

उन्होंने कहा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोप सहमति से बने संबंध को बलात्कार के रूप में स्थापित करने के लिए लगाए गए थे, ताकि आरोप लगाने वाली महिला और उसके परिवार को समाज के तानों का सामना न करना पड़े।

जस्टिस महाजन ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, कानून बेशक केवल चुप्पी को सहमति नहीं मानता, लेकिन यह उचित संदेह से परे सबूतों के अभाव में दोषी भी नहीं ठहराता। इस मामले में संदेह बना हुआ है - अटकलों के कारण नहीं, बल्कि सबूत के अभाव के कारण। हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे के दौरान न सिर्फ महिला के बयानों में विरोधाभास पाया गया, बल्कि दुष्कर्म की पुष्टि करने के लिए मेडिकल और फोरेंसिक सबूत भी नहीं मिले।

दिल्ली के शाहीनबाग में उड़ाए जा रहे ड्रोन, जामिया नगर से जामा मस्जिद तक पुलिस ही पुलिस

नईदिल्ली, एजेंसी।
लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधित विधेयक पास होने के बाद दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के शाहीनबाग में जहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है तो जामिया नगर से जामा मस्जिद तक मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। बिल पास होने के बाद पहला जुमा होने की वजह से मस्जिदों के आसपास भी निगरानी बढ़ी दिखी। दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड ऐक्शन फोर्स ने भी अलग-अलग इलाकों में फ्लैग मार्च किया। गलियों और बाजारों से एक साथ सैकड़ों सुरक्षाकर्मी यह संदेश देते हुए निकले कि गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वालों पर सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। जामिया नगर, जामा मस्जिद, मुस्तफाबाद, जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आए। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं। कंट्रोल रूम से हर इलाके की निगरानी की जा रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर किसी तरह के प्रदर्शन या उपद्रव की स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया। विश्वविद्यालय के गेट संख्या 7 के पास काफी संख्या में सीआरपीएफकर्मी तैनात दिखाई दिए। इसके अलावा पुलिस वैन इत्यादि के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात दिखे। यहां किसी भी तरह के प्रदर्शन, विरोध या असामान्य तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली।

उपद्रव से निपटने के इंतजाम किए गए। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में खामोशी छाई रही। वहीं, कुछ स्थानों पर अलग-अलग संगठनों ने मिठाई बांटकर खुशी भी जताई। इस बीच, संवेदनशील इलाकों में सुबह से सुरक्षाबल मुस्तैद नजर आए। सुरक्षाबलों ने शाम को फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का अहसास कराया। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने वक्फ बिल के विरोध में दिल्ली से आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने शाहीनबाग की ओर इशारा करते हुए कहा था कि आंदोलन की शुरुआत वहीं से होगी जहां खत्म हुई थी। बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीनबाग में महिलाएं लंबे समय तक धरने पर बैठी रही थीं।

दिल्ली में जल्द पेपर और फेसलेस की मिलेगी सुविधा

रेखा गुप्ता सरकार बना रही प्लान; आपको क्या होगा फायदा

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार अगले कुछ महीनों में संपत्तियों की सेल डीड के रजिस्ट्रेशन को पेपर और फेसलेस बना सकती है। नए सिस्टम में अधिकारियों और नागरिकों दोनों के लिए सभी निषिद्ध संपत्तियों की सूची भी उपलब्ध होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें धोखाधड़ी से बेचा न जाए और इनके सेल डीड पंजीकरण को रोका जा सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) आशीष चंद्र वर्मा ने गुरुवार को सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की, जिसमें शहर के नागरिकों के लिए संपत्तियों की सेल डीड के पंजीकरण को सुविधाजनक और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग ने प्रक्रियाओं को मैप करने और सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए संभावित समाधान सुझाने के लिए डेलॉइट को सलाहकार के तौर पर शामिल किया है। पोर्टल में नागरिकों के लिए एक ड्रॉप-डाउन मॉड्यूल भी होगा, जिससे वे निषिद्ध संपत्तियों - विवादित, शत्रु, ग्राम सभा भूमि और वक्फ के अलावा अवैध निर्माण के लिए नागरिक एजेंसियों द्वारा बुक की गई संपत्तियां को आसानी से ढूंढ सकेंगे। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, वर्मा ने कहा, हम चाहते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से फेसलेस हो और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप न हो। इसके लिए हमें तकनीकी बदलाव और कियोस्क स्थापित करने होंगे। जहां लोग जाकर पंजीकरण करा सकें और दस्तावेज अपलोड कर सकें। वर्मा ने कहा कि यह परियोजना नई सरकार की प्राथमिकता है और इसे इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली ने सब-रजिस्ट्रारों द्वारा सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत और 25 अन्य ऐसे दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) का उपयोग करना शुरू कर दिया है। सेल डीड पंजीकरण पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को एमसीडी के मूल्यांकन और संग्रह विभाग की ऑनलाइन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

मायावती ने वक्फ विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने की आलोचना की

नईदिल्ली, एजेंसी। बसपा नेता ने विधेयक पारित करने में सरकार की ''जल्दबाजी'' पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने जल्दबाजी में इस विधेयक को पेश किया और पारित कराया, जो उचित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि इस विधेयक को जनता की चिंताओं एवं शंकाओं को दूर करने के बाद ही पेश किया जाना चाहिए था। उनकी यह टिप्पणी बृहस्पतिवार देर रात को राज्यसभा द्वारा विधेयक को पारित करने के बाद आई। विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है, जहां विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया था। मायावती ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''संसद में वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार अगर जनता को इस विधेयक को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके इस विधेयक को लाती, तो बेहतर होता।

भाजपा के आते ही 82 तक बढ़ गई स्कूलों की फीस, बच्चों को परेशान कर रहे

नईदिल्ली, एजेंसी।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर बिजली कटौती के बाद अब एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। मामला स्कूलों की फीस से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज का दावा है कि भाजपा के आते ही स्कूलों की फीस भी बढ़नी शुरू हो गई है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने बिजली कटौती के बाद अब मिडिल क्लास पर दूसरा बड़ा प्रहार किया है। एक अप्रैल से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है।

उन्होंने कहा कि ये तकरीबन हर स्कूल में हुआ है। कहीं पर 20 तो कहीं पर 40-65 फीसदी स्कूल की फीस बढ़ा दी गई है। उनका दावा है कि कहीं तो यह आंकड़ा 82 फीसदी तक भी पहुंच गया है। उन्होंने कहा, एक अखबार के मुताबिक एक नामी स्कूल की द्वारका, वसंत कुंज और रोहिणी ब्रांच में फीस बढ़ाने के बाद बच्चों को परेशान किया जा रहा।

जिन बच्चों के माता-पिता ने बढ़ी हुई फीस नहीं दी, उन्हें लाइब्रेरी में बैठा दिया जाता है। टॉयलेट जाने के लिए भी उन्हें अटेंडेंट के साथ भेजा जा रहा है ताकी बच्चे क्लास में जाकर पढ़ाई ना करने लगे। उन्होंने कहा, इन स्कूलों में पढ़ने वाले मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं और उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अखबार के मुताबिक एक छात्र को दूसरे छात्रों ने चिढ़ाया कि तुम्हारा बाप बढ़ी हुई फीस भी नहीं दे सकता। सौरभ भारद्वाज ने अखबारों का हवाला देते हुए कहा, मयूर विहार फेज 3 के अंदर सालवन पब्लिक स्कूल ने कहा है कि ये 82 फीसदी फीस बढ़ाएगा। 57 फीसदी बढ़ा दी है और 25 फीसदी और बढ़ाएगा। जिन्होंने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है, उनके रिजल्ट रोक लिए गए हैं। माता-पिता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह उन्हें अन्य कई स्कूलों के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, केजरीवा सरकार के दौरान अगर फीस बढ़ती तो पहले विधायक स्कूल के बाहर पहुंच जाता था लेकिन बीजेपी के विधायक बच्चों के परिजनों क साथ खड़े नहीं दिखे। सौरभ भारद्वाज ने दावा कि पिछले 10 सालों में जो प्राइवेट स्कूल माफिया खत्म हुआ था।

हरिधाम पर पांचदिवसीय हनुमत कथा महोत्सव 8 से 12 अप्रैल तक

महंत शुकदेवदास महाराज के सानिध्य में हुआ भूमि पूजन शहरी क्षेत्र के साथ 25 गांवों के श्रद्धालु भी आएंगे

इंदौर

हवा बंगला कैट रोड स्थित हरिधाम पर 8 से 12 अप्रैल तक होने वाले पांच दिवसीय श्री हनुमत कथा महोत्सव के दिव्य आयोजन का भूमि पूजन आश्रम के अधिष्ठाता महंत शुकदेव दास महाराज के सानिध्य एवं समाजसेवी डॉ. सुरेश चौपड़ा, प्रकाश अजमेरा, विजयसिंह राणा एवं गोविंद मंगल के आतिथ्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ। महोत्सव का शुभारंभ सोमवार, 7 अप्रैल को फूटी कोठी से हरिधाम तक भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। आयोजन समिति के सुधीर अग्रवाल एवं मुकेश बृजवासी ने बताया कि हरिधाम पर 8 से 12 अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह 8 से 12 बजे तक श्री हनुमत महायज्ञ एवं दोपहर 2 से 5 बजे तक प्रख्यात मानस मनीषी पं. पुष्पानंदन पवन तिवारी के श्रीमुख से हनुमत कथामृत की वर्षा होगी। कथा स्थल पर भक्तों की सुविधा के लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। भूमि पूजन प्रसंग पर ओमप्रकाश अग्रवाल, श्रीकांत शर्मा, सीताराम नरेड़ी, संजय अग्रवाल, संतोषसिंह सहित बड़ी संख्या में हरिधाम से जुड़े श्रद्धालु मौजूद थे। हनुमत महायज्ञ का अनुष्ठान आश्रम परिसर में समाजसेवी प्रहलाद गर्ग परिवार द्वारा नवनिर्मित यज्ञशाला में होगा। इस अनुष्ठान में शहरी क्षेत्रों के साथ ही आसपास के 25 गांवों के श्रद्धालु भी शामिल होंगे। हनुमत कथा शुभारंभ के पूर्व सोमवार, 7 अप्रैल को सांय 4 बजे फूटी कोठी से हरिधाम तक भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। महोत्सव के समापन पर 12 अप्रैल को शाम 6 बजे से विशाल भंडारा भी होगा।